Yes, Sir. In August, 1990, Asian Development Bank had proposed assistance to an India Equity Fund (IEF), to be launched jointly with Unit Trust of India. The principal investment objective of the Fund is long term capital appreciation through investment in equity and convertible debenture issues of Indian Companies, particularly the issues of new companies.

कच्छ क्षेत्र में तस्करी

2946. **डा० बापू कालदाते:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कच्छ की खाड़ी अवैध व्यापार का केन्द्र बन गई है;

(ख) इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है;

(ग) वर्ष 1991 के दौरान सीमाशुल्क विभाग द्वारा जब्त की गयी तस्करी की वस्तुओं का मूल्य क्या है तथा उनकी मात्रा क्या है तथा इसमें शामिल उन लोगों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध अभियोग चलाये गये; और

(घ) सरकार समुद्र तट रेखा क्षेत्र की निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (घ): उपलब्ध रिपोर्टों तथा किये गये अभिग्रहणों से पता चलता है कि कच्छ की खाड़ी सोने और चांदी सहित निषिद्ध माल की तस्करी के लिए सुगम्य बनी हुई है। वर्ष 1991 के दौरान, कच्छ की खाड़ी पर क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा लगभग 39.72 करोड़ रुपये मूल्य का माल जब्त किया गया था और 51 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये थे।

सीमाशुल्क प्राधिकारी कच्छ की खाड़ी सहित तस्करी सबंधी गतिविधियों के प्रति सर्तक रहते हैं। आसूचना तंत्र को तस्करी के प्रति चुस्त कर दिया गया है और समुद्री तथा सड़क मार्गों की लगातार गश्त की जाती है। तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने में लगी सभी संबंधित एजेंसियों के बीच घनिष्ट तालमेल बनाए रखा जाता है।

Bank Employees Federation of India opinion against Narasimham Committee report

2947. SHRI BEKAL UTSAHI:
SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of the General Secretary, Bank Employees Federation of India, regarding the various recommendations of the Narasimham Committee, especially those regarding expansion of capital base of nationalised banks and rural branches thereof and deployment of bank resources and priority sector advances; and

(b) if so, what is the Government's reaction thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) No representation has been received from the General Secretary, Bank Employees Federation of India in regard to the recommendations of the Committee on the Financial System (Narasimham Committee).

(b) Does not arise.

Concept of non-voting shares

2948. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have examined the concept of non-voting shares; and

(b) if so, what is the reaction of Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) The Study Group under the Chairmanship of Shri M.J. Pherwani for reviewing the existing guidelines relating to capital issues and for evolving guidelines for issue of new financial instruments has recommended the introduction of non-voting shares. Section 85 of the Companies Act, 1956 provides for only two kinds of share capital. Accordingly, the Department of

Company Affairs which is administering the Act has been requested to examine and process the recommendation.

I.M.F. conditionalities and delicencing of industries

2949. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that IMF had put certain conditions on our economy like devaluation of rupee, free entry to multinationals and more than 51 percent equity in Indian industries to foreign nationals and curbing various rules on free import policy and delicencing of various industries;

(b) if not, what are the reasons for Government deviating from the earlier policy of self reliance;

(c) what is the share of foreign companies in our industrial production; and

(d) whether there is any restriction on the export of particular products manufactured by multinationals in India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) No, Sir.

(b) The Government is not deviating from its policy of self-reliance.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) Exports from India are regulated by the Import and Export (Control) Act, 1947, and the policies and procedures laid down in the Import and Export Policy. No distinction is made between companies having foreign equity participation, or those with 100% Indian equity for purposes of export of various products manufactured by them.

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन वितरित ऋणों में कदाचार

2950. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आदिवासी मंडला जिले की डिंडौरी तहसील और शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित बैंकों द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन लाखों रुपयों के ऋण वितरित किए जाने में हुए कदाचार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो जिन बैंकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनके नाम क्या-क्या हैं;

(ग) उन व्यापारियों के नाम क्या-क्या हैं जिनके लिए उक्त बैंकों को ऐसा लेन-देन करना पड़ा;

(घ) क्या सरकार ने इस कदाचार में शामिल बैंक अधिकारियों तथा व्यापारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को प्राप्त राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मंजूरी और संवितरण तथा कथित अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों को संबंधित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उठाया जाता है। बैंक आवधिक अंतरालों पर अपनी शाखाओं का निरीक्षण करते है। भारतीय रिजर्व बैंक भी बैंकों की सांविधिक जांच करता है निरीक्षण की इन प्रक्रियाओं के दौरान ऋण मूल्यांकन और अन्य मामलों से संबंधित विभिन्न कमियां सामने आती हैं। निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार बैंकों द्वारा अधिकारियों सहित दोषी पाये गए कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

Bid to take over Vysya Bank

2951. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that leading foreign bank is cornering a large part of the public shareholding of the Vysya Bank, one of the best-run private sector banks in the country; and

(b) if so, what steps Government are taking to protect the interests of this premier private sector bank and prevent its takeover by the said foreign bank?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) Reserve Bank of India have reported that they do not have information to this effect.